P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-6* September- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में नियोजन का शोधपरक अध्ययन

धर्मेन्द्र कुमार खटीक
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत के नियोजन का विस्तार से अध्ययन किया गया है। अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर ध्यान दिए बगैर भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। विकास के लिए अपनाये गए विभिन्न कार्यो के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विकास में परिवर्तन आया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुई है। फसल, उत्पादन, ग्रामीण, विद्युतीकरण, ग्रामोद्योग, शिक्षा, रक्षा, पुलिस के विकास कार्यो के प्रति अनुकूल अनुक्रिया, परिवहन, वृक्षारोपण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नियोजन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कृषि विकास भूमिहीनों के लिए उचित मजदूरी, औद्योगिकीकरण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा आर्थिक व सामाजिक उन्नति का आधार तैयार करना सम्मिलित है।

मुख्य शब्द : कृषि, नियोजन, रोजगार, पंचवर्षीय योजनाएँ, नीति आयोग।

प्रस्तावना

भारत में नियोजन

नियोजन दिशा निर्देषित सामाजिक परिवर्तन का एक प्रारूप है। परिवर्तन एक मूल्य विहीन अवधारणा अर्थात् यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही दिशा में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः परिवर्तन को वांछनीय दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजन अनिवार्य हो जाता है। नियोजन के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नीति निर्धारण के माध्यम से साधन भी सुनिश्चित किए जाते है। 200 वर्षो से भी ज्यादा के ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई। सामाजिक व्यवस्थाएँ भी प्रभावित हुई। अतः देश किस दिशा में आजादी के बाद अग्रसर हो यह तय करना कठिन हो गया। चूँकि एक राष्ट्र एवं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिपक्व नहीं हो सका था। परिवर्तन की बाजारी ताकतों पर छोड़ना संभव नहीं था। अतः देश के पास नियोजन की एकमात्र उचित विकल्प था। इस उद्देश्य से कार्यपालिका के आदेश से वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। 1962 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई एवं 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई।

योजना आयोग के स्थापना के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे–

1. देश में उपलब्ध भौतिक एवं अभौतिक संसाधनों की समीक्षा।
2. देश में उपलब्ध भौतिक एवं अभौतिक संसाधनों के उचित उपयोग की व्यवस्था।
3. सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन को दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित करना एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से मार्ग प्रशस्त करना।

यद्यपि योजना आयोग न तो एक संवैधानिक और ना ही एक वैद्यानिक निगम थी। परंतु यह अत्यधिक शक्तिशाली थी। ऐसा क्योंकि कयोजना आयोग एवं NDC दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

भारत में नियोजन से संबंधित स्थूल रेखाचित्र (Blueprint) आजादी से पूर्व ही बनाए जाने लगे है। इन स्थूल रेखाचित्रों में से एक महत्वपूर्ण नियोजन व्यवस्था G.D. Birla एवं J.R.D. Tata जैसे 8 प्रसिद्ध उद्योगपति हो " Bombay Plan" प्रतिपादित किया। (1944) इसी वर्ष Narayan Agarwal ने " Guardian Plane" प्रतिपादित किया जो गांधीवादी विचारधाराओं पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करना था। 1945 में M.N. Roy us " Peoples Plan" प्रतिपादित किया। जो कि साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी।

1950 में J.P Narayan ने " Garvadya Plane" प्रतिपादित किया। जो कि समावेशी विकास एवं विकास का लाभ समाज के निम्न स्तर तक पहुँचाने का

उद्देश्य रखती थी। परंतु भारत में प्रारंभिक दौर में " Nefire-Mahabisobis" उपागम नियोजन की प्रक्रिया का आधार बना। यह उपागम Russia की व्यवस्था से प्रेरित था, जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लागू किया गया। जबकि Bombay Plan, Japan के व्यवस्था से प्रेरित थी।

Bombay Plane

Bombay Plan, G.D. Birla, J.R.D. Tata जैसे 8 प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने 1944 में प्रतिपादित किया था। यह श्रंचंद के तर्ज पर तैयार किया गया था। इसके अर्न्तगत यह सुझाव दिया गया कि भारत तत्कालीन रूप से हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास ना करें। भारत उन्हीं आर्थिक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करे जिमें वह सक्षम अथवा तेज है। जैसे उत्पादों कर निर्यात कर प्रेरित विदेशी पूंजी से अन्य आवश्यकताएँ आयात के माध्यम से पूरी की जाए। यह मुख्यतः इसलिए क्योंकि भारत में संसाधन पूंजी एवं प्रौद्योगिकी तथा र्निपेक्षों की कमी रही है।

Nehru-Mahabinobis Approach

यह उपागम पं. जवाहर लाल नेहरू एवं पी. महलनोविस ने प्रतिपादित किया था। इसे Trickle Down अथवा Topodown अथवा निश्यंदन का उपागम कहते हैं। अर्थात विकास उपरी सतह पर की जाए एवं लाभ निम्न स्तर तक पहुँचे। आत्मनिर्भर होने का सुझाव दिया। इस उपागम ने भारी कारखानों की स्थापना कर सुझाव दिया जिनके माध्यम से उन मशीनों व उपकरणों का उत्पादन हो सकें, जो पुनः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में मददगार सिद्ध होंगे। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था रखा जाय जिसमें न तो विदेशी निवेश की अनुमति होगी और ना ही घरेलू निवेशकों को विदेश की अनुमति होगी। निजी निवेश एवं सार्वजनिक निवेश दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाए परन्तु सभी सामाजिक क्षेत्र सरकार के ही नियंत्रण में रहे।

अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था समझा जाए जिसका रूझान सार्वजनिक निवेश की ओर ज्यादा हो। रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए लघु उद्योग की स्थापना व विस्तार किया जाये।

अध्ययन का उद्देश्य

नियोजन को किस तरह अपनाया गया है।

1. नियोजन हेतु विभिन्न मॉडलों की प्रांसगिकता
2. योजना आयोग से NITI को बदलने के मायने।

शोध विधि

1. द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है
2. विभिन्न रिपोर्टो तथा साहित्य आधारित शोध विधि को अपनाया है।

भारत में आयोजन

Planning in India

इस प्राखण्ड में हम भारत की पंचवर्षीय विकास योजना का परीक्षोपयोगी वृद्धि से अध्ययन् करेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–55)

भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1951 से प्रारम्भ हुई। यह योजना डोमर संवृद्धि मॉडल पर आधारित थी। योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। ध्यातव्य है कि इसी योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारम्भ की गई। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुण्ड जैसी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं इसी योजना की देन हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)

पी.सी. महालनोविस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत तथा भारी उद्योग प्रधान योजना थी। राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (छत्तीसगढ़), एवं दुर्गापुर (पं. बंगाल) इस्पात संयंत्रों की स्थापना के साथ इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव्स भी इसी योजना की देन थी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था को 'आत्म निर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान' Take of Stage बनाए जाने पर जोर।
2. भारत–चीन युद्ध (1962), भारत–पाक युद्ध (1965) और 1965–66 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रही।
3. इस योजना में रूपये को अवमूल्यित किया गया।
4. 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) और इंडस्ट्रियल डेवलमेंट बैंक ऑफ (IDBI) की स्थापना की गई।
5. 1965 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) और कृषि कीमत आयोग (APC) की स्थापना की गई।
6. पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 'ट्रिकल डाउन थियरी' का अनुसरण किया।

तीन पंचवर्षीय योजना (1966–69)

1. भारतीय योजनावधि में इस अवधि (1 अप्रैल, 1966–31 मार्च, 1969) को 'योजनाकाश (Plan Holiday) की संज्ञा दी जाती है।
2. 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश के आधार पर 'लीड बैंक योजना' की शुरूआत की गई।
3. कृषिगत संकट को रोकने और खाद्यात्र की कमी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र पर जोर।
4. तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान पूरी तरह से एक नई कृषि नीति अपनाई गई और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज के वितरण, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार व भू–संरक्षण आदि विधियों पर विशेष जोर दिया गया।
5. 1966–67 के दौरान भारत में हरित–क्रांति की शुरूआत।

चौथी पंयवर्षीय योजना (1969–74)

1. योजना का मुख्य उद्देश्य 'स्थिरता के साथ आर्थिक विकास' (Growth with stability) तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति (Progress Towards self Reliance)
2. इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया किया गया।
3. जुलाई, 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण।

4. 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण (स्माइलिंग बुद्धा) किया गया।
5. भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना से लियोंटिफ के आगत–निर्गत मॉडल (Input-Output Model) को लागू किया गया।
6. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) की 1973–74 में शुरूआत
7. परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)

1. योजना का मुख्य उद्देश्य 'गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करना। था।
2. जनता सरकार से सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1978 (1979 के स्थान पर) में ही बंद कर दिया गया।
3. यह योजना डी.पी. धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया।
4. 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
5. 2 अक्टूबर, 1976 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (R.R.B.) की स्थापना की गई।
6. 1977–78 में ''खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम'' की शुरूआत की गई।
7. केन्द्र सरकार द्वारा 1977–79 में राजस्थान राज्य में 'अत्योदय योजना' प्रारम्भ की गई।

अनवरत योजना (1978–80)

1. जनता सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले (1974–78) समाप्त करके एक नई योजना को 1 अप्रैल, 1978 को पेश किया गया, जिसकी संज्ञा, 'अनवरत योजना' (Rolling Plan) थी। इसका प्रतिपादन गुनार मिर्डल ने किया था और भारत में इसको पांचवी योजना दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. डी.टी. लकड़ावाला ने लागू किया था।
2. 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरूआत की गई, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया।
3. दो बार छंटी योजना की शुरूआत हुई। पहली बार जनता सरकार (1978–83) द्वारा जो केवल दो वर्ष तक ही चल सकी और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 में शुरू की गई।

छठीं पंचवर्षीय योजना (1980–85)

1980 में कांग्रेस के केन्द्र में पुनः सत्तारूढ़ होने पर कांग्रेस सरकार ने 1978–83 की योजना के स्थान पर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) लागू की थी। इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। IRDP, NERP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP जैसी ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में छठीं योजना में ही लागू किये गये। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा 'गरीबी निर्देशांक' अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया।

योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी एवं बेरोजगारी में लगातार कमी करना, परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या नियंत्रण।

1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 में ही एक्जिम बैंक स्थापित हुई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)

1. सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना रहा। इसके लिए खाद्यात्र उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता व रोजगार अवसरों में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया।
2. योजनावधि में अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड 5.6 प्रतिशत (लक्ष्य 5 प्रतिशत) के स्तर तक बड़ी।
3. 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट व्यवस्था की शुरूआत हुई।
4. सितंबर 1986 में नई दिल्ली में कपार्ट की स्थापना।
5. 1988 में सेबी की स्थापना।
6. अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (JRY) और सितंबर,1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरूआत।
7. प्रो. राजकृष्णा ने सातवीं योजना को हिन्दू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)

1. यह योजना आधारभूत ढांचे पर बल देने के रूप में परिणत जान डब्ल्यू. मुलर मॉडल पर आधारित थी। (IAS-10) योजना का मुख्य उद्देश्य था 'मानव संसाधन का विकास'
2. 1 जनवरी, 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना।
3. 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई।

वार्षिक योजना

1. राजनैतिक अस्थायित्व और भुगतान संतुलन संकट के कारण 1990–92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी।
2. लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने 1990 में सिड़वी (Small Industrial Development Bank of India-SIDBI) की शुरूआत की।
3. 1991 में भारत में आर्थिक सुधार (उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण) की घोषणा की गई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

1. योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक संवृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्म निर्भरता एवं क्षेत्रीय संतुलन जैसे चार क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)

1. दसवीं योजना में आर्थिक संवृद्धि का लक्ष्य 7.9 प्रतिशत, उपलब्धि 7-9% प्रतिशत, उपलब्धि 7-7% प्रतिवर्ष। 7.7 प्रतिशत की यह संवृद्धि अब तक की किसी भी योजनावधि में सर्वाधिक है।

2. 2007 तक गरीबी का अनुपात 26 प्रतिशत से घटाकर 21% तथा 2012 तक 15% बिन्दु तक लाना था।
3. सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में दाखिल करना और 2007 तक सभी बच्चों की स्कूली पढ़ाई को 5 साल पूरा करना।
4. 2007 तक शिशु मृत्तुदर को 45 प्रति हजार तक ओर 2012 में कम करके 28 प्रति हजार तक किया जाना।
5. मातृत्व मृत्युदर 2007 तक 2 प्रति हजार तथा 2012 तक 1 प्रति हजार तक पहुंचाना।
6. 2007 तक वानिकीकरण को 25 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाना।

11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)

1. दृष्टिकोण तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर।
2. जीडीपी वृद्धि दर– 7.8 प्रतिशत (लक्ष्य 9.0)
3. वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात 4.1
4. जीडीपी के अनुपात में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत (लक्ष्य – 4.0%) प्रतिवर्ष।
5. क्षेत्रवार सर्वाधिक वास्तविक परिव्ययः सामाजिक सेवाएं (32.7%) ,ऊर्जा (18.2%) एवं परिवहन (17.7%)

12वीं पंचवर्षीय येाजना–दृष्टिकोण पत्र

1. 27 दिसम्बर, 2012 को सम्पत्र राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दस्तावेज पत्र को स्वीकृति प्रदान किया गया। जिसके महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं। यथा
2. 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अवधारणा का केन्द्र बिन्दु है– तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास (Faster Sutainable and more Inclusive Growth)
3. वार्षिक औसत के आधार पर–
   i. G.D.P. वृद्धि दर = 8.0 %
   ii. कृषि क्षेत्रक वृद्धि दर = 4.0%
   iii. उद्योग क्षेत्रक वृद्धि दर = 9.6%
   iv. सेवा क्षेत्रक वृद्धि दर = 10.0%
   v. बचत दर G.D.P. का = 32.2%
   vi. निवेश दर = 38.7% लक्षित किया गया।
4. औसत वार्षिक केन्द्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना अवधि में ळण्क्ण्च्ण् के 3.25% के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया है।
5. औसत वार्षिक केन्द्रीय राजकोषीय घाटा। इस योजना अवधि में ळण्क्ण्च्ण् के 3.25 के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया है।
6. 12 वीं योजनावधि में चालू खाते के घाटे को G.D.P. के 2.5 % तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
7. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की औसत वार्षिक वृद्धि को 12 वीं योजना में 4.5 - 5.0 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य हैं।
8. 12 वीं योजनावधि में निर्धनता में 10 प्रतिशतांक की कमी लाना। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार का सृजन। विनिर्माण क्षेत्र में 10 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना। अवसंरचना में निवेश को GDP के 9.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य।
9. केन्द्र के लिए निवल राजस्व 12वीं योजनावधि में G.D.P. के 8.68 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो 2011–12 कि 7.4 प्रतिशत से 1.51 प्रतिशतांक अधिक है।
10. 12वीं योजनावधि कर निम्न राजस्व G.D.P के 1.01 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।
11. केन्द्रीय आयोजन व्यय 12 वीं पंचवर्षीय योजना में G.D.P. का 4.02 प्रति है।
12. आयोजना–भिन्न व्यय G.D.P. का 8.9 प्रतिशत अनुमानित है।
13. आधारभूत संरचना में आवश्यक निवेश का लक्ष्य = 1000 वि.डा

नियोजन के प्रारूप

नियोजन को मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. परिपेक्ष्य नियोजन (Prospective Plane)
2. चल नियोजन (Rolling Plane)
3. सांकेतिक नियोजन (Indicative Plane)

परिपेक्ष्य नियोजन दीर्घकालीन नियोजन को संबोधित करती है। इसके अंतर्गत 15–20 वर्षो के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते है एवं अन्य लक्ष्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से धीरे–धीरे आंशिक रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात् इन लक्ष्यों को छोटे–छोटे हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। यह एक दूरदर्शी नियोजन की प्रक्रिया है। चूंकि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है जिसमें अनिश्चितताएँ इसको प्रमुख चरित्रों में से एक होती हैं। भविष्य का अनुमान सरल नहीं होता है। अतः ऐसे नियोजन के असफल होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है।

चल नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 3 प्रकार के नियोजन समाहित होते है। एक दीर्घकालीन नियोजन जो कि 15–20 वर्षो के लिए होता है। दूसरा मध्यकालीन नियोजन जो पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में होता है एवं तीसरा अल्पकालीन नियोजन जो वार्षिक होता है।

इस नियोजन की प्रक्रिया में वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर संशोधित किया जाता है एवं मध्य कालीन तथा दीर्घकालीन तथ्यों को भी परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत में जनता सरकार द्वारा जारी पंचवर्षीय योजना इस श्रेणी में आती है। (छटी पंचवर्षीय योजना भारत में 2 बार जारी की गई थी। पहली जनता सरकार द्वारा व दूसरी इंदिरा सरकार द्वारा।)

सांकेतिक नियोजन मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था की आरे बढ़ना एक कदम है। भारत में इसे 8 वें एवं 9 वें पंचवर्षीय योजनाओं से लागू किया गया। इसके अंतर्गत सरकार कीभूमिका मात्र सुविधाएँ प्रदान करने तक सीमित रह जाती है। अन्य सांकेतिक अथवा अनुमानित होते है एवं इन्हें प्राप्त करने के साधन बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिए जाते हैं। साथ ही इस पंचवष्रीय योजना के अंतिम 2 वर्षो में विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10ः के दर से बढ़ोत्तरी अनिवार्य होगी। 8% के वार्षिक वृद्धि दर के साथ–साथ देश में कार्बन उत्सर्जन को 2005 के स्तर तक लाने का निर्णय हुआ। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार

fastel sustainable and more inclusive growth (तीव्र –सतत् एवं अधिक समावेशी विकास) पर।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आजादी के उपरांत आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के उद्देश्य से दिशा निर्देशित परिवर्तन के उपकरण के रूप में नियोजन भारत में एकमात्र थी। नियोजन की यह प्रक्रिया देश में सफल व असफल भी रही। यद्यपि नियोजन की असफलताएँ व्यापक थी। इसकी सफलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

आजादी के दौरान भारत एक कृषिप्रधान देश था जिसका योगदान GDP में 50% से ज्यादा था। देश की 2/3 जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर आश्रित थी। वर्तमान में कृषि का योगदान हटाकर मात्र 13.9% रह गया है जबकि कृषि क्षेत्रों में उत्पादन लगातार बढा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य दो क्षेत्रों का योगदान (उद्योग एवं सेवाक्षेत्र) और तेजी से बढ़ा है जो कि नियोजन की सफलता का एक प्रमाण है। आजादी के दौरान भारत अनाज का निवल आयात था, परन्तु वर्तमान में भारत न सिर्फ अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि यह अनाज का निवल निर्यातक भी है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर एवं अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्थाएं सबसे तीव्र गति से अग्रसर अर्थव्यवस्था है। भारत G.D.P के आधार पर विश्व की 7 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि क्रय क्षमता तुमना (PPP) के आधार पर यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आजादी के दौरान देश में 60% से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है जो कि छाटकर मात्र 21.94% रह गई है। आजादी के दौरान भारत में जीवत प्रत्यक्ष मात्र 32–33 वर्ष की थी जो कि स्वस्थ एवं चिकित्सा की सुविधाओं में सुधार के कारण 66 वर्ष से ज्यादा हो गई है। भारत निवेश के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण देश बन गया तथा यह विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *मीणा विजय सिंह (2009): राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास उदयपुर जिले का भौगोलिक अध्ययन, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर*
2. *नाथूराम का लक्ष्मीनारायण (2009): इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर*
3. *जय अल्पना सिंह ने 2013 में गरीबी लिंग तथा सामाजिक विकास शोध किया है।*
4. *भारत ईयर बुक, 2017*
5. *आर्थिक समीक्षा 2017*
6. *cencus.2011.co.in.*
7. *www.planingdept.gov.in*
8. *भारतीय अर्थव्यवस्था: मिश्रा एण्ड पुरी*